अध्याय - 4 संस्थाओं का कामकाज

स्मरणीय तथ्य

- लोकतन्त्र में जब जनता शासकों का चुनाव करती है तो ये चुने हुए शासक संस्थाओं के माध्यम से शासन का संचालन करते हैं।
- संविधान के द्वारा शासन के मूल्यों के निर्धारण के साथ संस्थाओं के कार्यों और संस्थाओं की कार्य सीमा का भी निर्धारण किया जाता है ।
- भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिए 27 % स्थान आरक्षित किया गये ।
- इससे पहले आरक्षण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (S.C./S.T.) को ही दिया जा रहा था।
- भारत सरकार द्वारा 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया जिसकी अध्यक्षता वी.पी. मंडल (विंदेश्वरी प्रसाद मण्डल) ने की। इसी कारण इसे मंडल आयोग कहते हैं ।
- पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया ।
- मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें 1980ई. में प्रस्तुत की जिसमें प्रमुख थी, सरकारी नौकरियों में सामाजिक, और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण देना ।
- दूसरा पिछड़ी जाति आयोग :
  - 1979 में गठित।
  - अध्यक्ष - बी. पी. मंडल ।
  - 8 सितम्बर 1993 में पूरी तरह लागू ।
- **संस्था :** नागरिको की आधारभूत सुविधाएँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास,कल्याण परक सुविधाएँ नागरिकों को प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं को ही संस्था / संस्थाएँ कहा जाता है ।
- संसद : भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं ।
- **संसद :** संसद एक ऐसा मंच है जहाँ पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून / विधि निर्माण का कार्य करते हैं ।
- संसद के दो सदन होते हैं : a. लोकसभा b. राज्य सभा
- संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यताएं:
  - भारत का नागरिक हो ।
  - सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत न हो।
  - दिवालिया या सज़ायाफ्ता न हो ।
- संसद के राजनैतिक अधिकार :
  - कानून बनाने, संशोधन करने तथा पुराने कानून की जगह नये कानून बनाने का अधिकार ।
  - सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने का अधिकार ।
  - सरकार के हर पैसे पर नियंत्रण का अधिकार ।
  - सार्वजनिक मामलों व राष्ट्रीय नीति पर चर्चा का अधिकार ।
- लोकसभा (हाउस ऑफ पीपल / लोअरहाउस): लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं । इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जो स्पीकर कहलाता है । इसके सदस्यों की संख्या 543 + 2 होती है। (2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है ।)
  - सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रुप से होता है।
  - मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण।
- राज्यसभा (काउंसिल ऑफ स्टेट्स / अपर हाउस): राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है । इसके सदस्यों की कुल संख्या 250 है जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ।
  - सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
  - मंत्रिपरिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं।
  - राज्यों के सम्बन्ध में विशेष अधिकार।
- लोकसभा और राज्य सभा में अंतर :
  - लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है।
  - राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है।
  - संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है।
  - लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारो का प्रयोग करती है।
  - लोकसभा मंत्रिपरिषद् को नियंत्रित करती है । राज्यसभा को यह अधिकार नहीं ।
- **कार्यपालिका :** सरकार की नीतियों को कार्यरूप देनेवाले को कार्यपालिका या सरकार कहते हैं।
- कार्यपालिका के दो हिस्सा होते हैं :-
  - राजनैतिक कार्यपालिका :- प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद् मिलकर राजनैतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं। मंत्रीपरिषद् का काम होता है सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को मूर्त रूप देना या क्रियान्वयन करना। इसलिए मंत्रीपरिषद् को कार्यपालिका कहा जाता है। राजनैतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं।
  - स्थायी कार्यपालिका :- यह नौकरशाहों से मिलकर बनी होती है । नौकरशाहों का चयन अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज द्वारा होता है। सरकारें बदलने के बावजूद नौकरशाहों यानी स्थायी कार्यपालिका के कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं आती है ।
- प्रधानमंत्री:- प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और वास्तव में सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। वह देश की सबसे

महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता ।वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जबतक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है ।

- राष्ट्रपति:- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है जो बहुमत या गठबंधन या सदन में जिनको बहुमत हासिल हो, की सरकार बनती है ।
- मंत्रिपरिषद् :- मंत्रिपरिषद् उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं । इसमें आम तौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं ।
- मंत्रियों की रैंक इस प्रकार है :-
  - कैबिनेट मंत्री :- अक्सर सत्ता दल के शीर्ष नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। उन्हें प्रमुख मंत्रालयों का भार दिया जाता है। परिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग 25 होती है ।
  - स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री :- इन्हें अक्सर छोटे मंत्रालयों का भार दिया जाता है । ये केवल निमंत्रण मिलने पर ही कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं।
  - राज्यमंत्री :- अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं।
- भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार :-
  - कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता।
  - विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय ।
  - विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी।
  - मंत्रियों के कामों का वितरण।
  - किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार ।
- राष्ट्रपति : भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं ।
  - सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम से लिया जाता है।
  - जब कोई बिल संसद से पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही वह कानून बन पाता है।
  - सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है ।
  - सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं।
- भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं :-
  - भारत का नागरिक हो ।
  - आयु 35 वर्ष से अधिक हो ।
  - दिवालिया या सजायाफ्ता न हो ।
  - सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत न हो ।
  - लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो ।
- न्यायपालिका :- एक महत्वपूर्ण संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निबटारे का अधिकार होता है । देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है ।
- न्यायपालिका के अधिकार :- इसके पास न्याय करने का अधिकार और कानूनी विवादो के निबटारे का अधिकार होता है ।
- भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों के नाम :-
  - पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय ।
  - राज्यों में उच्च न्यायालय।
  - जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के न्यायालय ।
- गठबंधन सरकार:- विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनैतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार।
- कार्यपालिका: व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फ़ैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है।
- सरकार:- संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन-जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है।
- विधायिका:- जन प्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है।
- कार्यालय ज्ञापन:- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फ़ैसले या नीति के बारे में बताया जाता है।
- राजनैतिक संस्था:- देश की सरकार और राजनैतिक जीवन के आचार को नियमित करनेवाली प्रक्रियाओं का समूह।
- आरक्षण:- भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में पद एवं सीटें 'आरक्षित' करने की नीति ।
- राज्य:- निश्चित क्षेत्र में फैली राजनैतिक इकाई, जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। 'राज्य' शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाईयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय स्तर पर "भारत की सरकार" को और किस नाम से जाना जाता है ?

a. केन्द्र/संघ की सरकार
b. राज्य सरकार
c. पंचायत की सरकार
d. नगरपालिका की सरकार

2. भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया?

a. 1969 ई. b. 1979ई.

c. 1985ई. d. 1990 ई.

3. दूसरा पिछड़ा जाति आयोग का अध्यक्ष कौन था?

a. हर्षा चौहान b. विजय सांपला
c. बी०पी० मंडल d. डॉ भीम राव अम्बेडकर

4. दूसरा पिछडा जाति आयोग को किस नाम से जाना जाता है?

a. मंडल आयोग b. कमंडल आयोग
c. योजना आयोग d. स्वर्ण सिंह आयोग

5. मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की?

a. 17% b. 25%
c. 30% d. 27%

6. 1989 ई. के लोकसभा चुनाव के बाद किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनी ?

a. कांग्रेस पार्टी b. जनता दल
c. भारतीय जनता पार्टी d. बहुजन समाजवादी पार्टी

7. 1989 ई. के लोकसभा चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने ?

a. राजीव गांधी b. इंद्र कुमार गुजराल
c. अटल बिहारी वाजपेयी d वी० पी० सिंह

8. इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला संबंधित है –

a. पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने से संबंधित
b. अनुसूचित जातियों को के आरक्षण से संबंधित
c. अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित
d. इनमें से कोई नहीं।।

9. पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने संबंधी भारत सरकार के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ठहराया ?

a. अवैध b. वैध
c. फैसला नहीं दिया d. असंवैधानिक

10. भारत में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि कहाँ बैठक करते हैं?

a. विधान सभा में b. कांग्रेस में
c. ग्राम पंचायत में d. संसद भवन में

11. राज्य या प्रांतीय स्तर में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को क्या कहा जाता है ?

a. संसद b. राज्य सभा
c. विधानसभा d. लोकसभा

12. कानून बनाने या विधि निर्माण करने का कार्य करती है-

a. कार्यपालिका b. न्यायपालिक
c. राष्ट्रपति d. विधायिका

13. सरकार की नीतियों को कार्यरूप या लागू करने का कार्य करती है –

a. कार्यपालिका b. न्यायपालिका
c. राज्यपाल d. विधायिका

14. कानून की समीक्षा और रक्षा करती है

a. न्यायपालिका b. राष्ट्रपति
c. विधायिका d. कार्यपालिका

15. संसद क्या कार्य कर सकती है?

a. नए कानून बना सकती है।
b. मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है।
c. मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नये कानून बना सकती है।
d. उपरोक्त सभी।

16. भारतीय संसद के अंग है –

a. लोकसभा b. राज्य सभा
c. राष्ट्रपति d. उपरोक्त सभी

17. हमारे देश के संसद में कितने सदन हैं?

a. चार b. दो
c. तीन d. एक

18. संसद के दोनो सदनों का नाम क्या है?

a. लोकसभा और राज्यसभा
b. लोकसभा और विधान सभा
c. राज्यसभा और राष्ट्रपति
d. विधान सभा और नगरपालिका

19. संसद के फैसले किसकी मंजूरी के बाद लागू होते है ?

a. प्रधानमंत्री b. राष्ट्रपति
c. राज्यपाल d. मुख्यमंत्री

20. वर्तमान में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव कराए जाते हैं?

a. 443 b. 500
c. 525 d. 543

21. राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या निर्धारित है?

a. 150 b. 200
c. 250 d. 300

22. राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनित करते हैं?

a. 10 b. 12
c. 15 d. 20

23. राज्य सभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है?

a. 14 दिन b. 20 दिन
c. 28 दिन d. 7 दिन

24. निम्न में कौन ब्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है ?

a. लोकसभा के विपक्ष का नेता
b. राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को भी चाहे
c. लोकसभा में बहुमत दल का नेता